Government to Assam during last three years, till date is given in the statement (see below).

(b) It is proposed to earmark 10% of the budget allocation to the North-Eastern States.

Statement

Release of funds under Rural Development Programmes to Assam during 1995-96, 1996-97, 1997-98 and 1998-99 (Till date)

(Rs. in lakhs)

Sl No.	Name of the Scheme	Release of funds by Central Govt. to Assam			
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	JRY	7719.76	3186.83	5524.15	4011.71
2.	EAS	8020.00	10820.00	8592.00	2488.00
3.	MWS	1143.53	1054.14	1210.22	723.35
4.	IAY	2656.32	3157.45	2931.07	3347.27
5.	IRDP	1537.96	1066.76	1425.63	1163.68
6.	DWCRA	158.85	180.89	136.16	118.88
7.	TRYSEM	81.57	105.45	104.33	71.22
8.	TOOLKITS	171.00	114.85	82.85	93.97
9.	NSAP	471.83	697.94	742.41	206.33
10.	ARWSP	2245.00	2353.57	2376.52	2485.48

*Including UNICEF

बंजर भूमि के विकास हेतु धनराशियों की सी०ए०जी० द्वारा लेखा परीक्षा

1208. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सी०ए०जी०) ने बंजर भूमि के विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशियों के संबंध में लेखा-परीक्षा की है; यदि हां; तो ऐसी लेखा-परीक्षा किस-किस वर्ष के लिए की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार ने बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का पुनरीक्षा, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करने के लिए कोई कारगर व्यवस्था की है; यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में बंजर भूमि विकास हेतु आवंटित धनराशियां प्राप्त करने वाले उन संगठनों के नाम क्या है जिनके संबंध में सी०ए०जी० द्वारा लेखा-परीक्षा की गई और क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आपत्तियां दर्ज की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा आर० पाटिल): (क) और (ख) जी, हां। बंजरभूमि विकास विभाग की स्थापना जुलाई, 1992 में की गई थी। विभाग के कार्यक्रमों की लेखा-परीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, के कार्यालय के द्वारा की जाती है। अभी तक लेखा-परीक्षा, 31 मार्च 1997 को समाप्त अवधि तक के लिए की गई है।

(ग) राजस्थान में वित्तपोषित किसी भी संगठन के सम्बन्ध में कोई भी लेखा-परीक्षा पैरा विभाग में लम्बित नहीं है।

NGOs blacklisted by Capart

1209. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether nearly 350 Non-Governmental Organisations (NGOs) were blacklisted by Council for Advancement